INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS

VOLUME 2, ISSUE 7, JULY 2014

ISSN-2320-2882

ORIGINAL ARTICLE

भारत में उद्यमिता विकास-कार्यक्रम एवं संगठन

हरिनारायण विश्वकर्मा, *अजय दीक्षित, शोध छात्र,
*अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, (म.प्र.)
*Email-harinarayan060788@gmail.com
**अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, (म.प्र.)
**Email-ajaydixit147@gmail.com

सारांश

उद्यमशीलता जीवन का एक आवश्यक अंग है। यह मानव जीवन का एक आधारभूत दर्शन एवं स्वभाव है, जो व्यक्ति को स्वभावत: कर्म करने हेतु प्रेरित करता है। यह मात्र धन सृजन का एक तरीका नहीं है, वरन् व्यक्तित्व एवं समग्र सामाजिक आर्थिक विकास का एक महामंत्र भी है। जो आत्मनिर्भरता एवं आत्मसहायता के साथ बेहतर रूप से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, एवं मानवीय प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त मार्ग प्रदान करता है। वस्तुत: उद्यमशीलता एक तकनीक कौशल एवं चिंतन के साथ एक जीवन पद्धति भी है। मानव अनादि काल से ही अपने जीवन यापन हेतु कर्मशील एवं उद्यमी रहा है। मनुष्य के कर्मशील व उद्यमी होने के प्रमाण हमें चीन, यूनान, बैबीलोनिया, एवं भारत आदि देशों की प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। वस्तुत: उद्यमी वर्ग का आविर्भाव १७ वीं शताब्दी से ही प्रारम्भ माना जाता है। उद्यमी वर्ग के आविर्भाव की अवस्थाओं में औद्योगिक क्रांतिकाल को एक स्वर्णिम युग कहा जाता है। १७ वीं एवं १८ वीं शताब्दी के मध्य काल में कुटीर व लघु उद्योगों के विकास से लेकर वृहत् स्तरीय स्वचालिका उद्योगों के विकास की श्रृंखला में उद्यमियों की अन्यानेक भूमिकाएं प्रकट हुई हैं।

आधारवाक्य- उद्यमिता विकास, कार्यक्रम एवं संगठन, औद्योगिक नीति।

प्रस्तावना- मानव अनादि काल से ही अपने जीवन यापन हेतु कर्मशील एवं उद्यमी रहा है। मनुष्य के कर्मशील व उद्यमी होने के प्रमाण हमें चीन, यूनान, बैबीलोनिया, एवं भारत आदि देशों की प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। वस्तुत: उद्यमी वर्ग का आविर्भाव १७ वीं शताब्दी से ही प्रारम्भ माना जाता है। उद्यमी वर्ग के आविर्भाव की अवस्थाओं में औद्योगिक क्रांतिकाल को एक स्वर्णिम युग कहा जाता है। १७ वीं एवं

Please cite this Article as : हरिनारायण विश्वकर्मा, अजय दीक्षित, **भारत में उद्यमिता विकास-कार्यक्रम एवं संगठन** : International Journal Of Creative Research Thoughts, Volume 2, Issue.7, July 2014

१८ वीं शताब्दी के मध्य काल में कुटीर व लघु उद्योगों के विकास से लेकर वृहत् स्तरीय स्वचालिका उद्योगों के विकास की श्रृंखला में उद्यमियों की अन्यानेक भूमिकाएं प्रकट हुई हैं। भारत का गौरवमयी इतिहास अपने पुरातन काल से ही कला कौशल, शिल्पकारिता एवं उद्यमीय दक्षता से ओतप्रेत रहा है। यहां की औद्योगिक कलात्मकता एवं शिल्पकला ने विश्वभर में प्रसिद्धी प्राप्त कर एक विशिष्ट व सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। साथ ही हमारी उद्यमशीलता एवं कलात्मकता ने विश्व बाजारों में सराहनीय व ख्यातिपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। हमारे देश में व्यवसायिक उद्यमिता, कलात्मकता व शिल्पकला के आविर्भाव की कहानी के सूत्रपात का श्रेय यहां की सामाजिक व्यवस्था, रीतिरिवाज, परम्पराएं, पारिवारिक प्रथाएं, धार्मिक दृष्टिकोण पूजा अर्चनाओं एवं शूरवीरों के बलिदानों की कथाओं को जाता है। जिनसे प्रभावित होकर हमारे शिल्पकारों ने वैचारिक व संवेदनशील तत्वों को बोधगम्य बनाकर अपनी कलात्मकता को नया स्वरूप प्रदान किया है। भारत में १६ वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों व व्यवसायियों में उद्यमीय वातावरण के प्रति संचेतना जागृत हुयी। साथ ही १७ वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय उद्यमियों ने अपनी कलाकृति, दस्तकारी व कौशलता के बल पर अनेक वस्तुएं विदेशों को निर्यात करना आरम्भ कर दिया था।

भारत में उद्यमिता का विकास– भारत का गौरवमयी इतिहास अपने पुरातन काल से ही कला कौशल, शिल्पकारिता एवं उद्यमीय दक्षता से ओतप्रेत रहा है। यहां की औद्योगिक कलात्मकता एवं शिल्पकला ने विश्वभर में प्रसिद्धी प्राप्त कर एक विशिष्ट व सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। साथ ही हमारी उद्यमशीलता एवं कलात्मकता ने विश्व बाजारों में सराहनीय व ख्यातिपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। हमारे देश में व्यवसायिक उद्यमिता, कलात्मकता व शिल्पकला के आविर्भाव की कहानी के सूत्रपात का श्रेय यहां की सामाजिक व्यवस्था, रीतिरिवाज, परम्पराएं, पारिवारिक प्रथाएं, धार्मिक दृष्टिकोण पूजा अर्चनाओं एवं शूरवीरों के बलिदानों की कथाओं को जाता है। जिनसे प्रभावित होकर हमारे शिल्पकारों ने वैचारिक व संवेदनशील तत्वों को बोधगम्य बनाकर अपनी कलात्मकता को नया स्वरूप प्रदान किया है। भारत में १६ वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों व व्यवसायियों में उद्यमीय वातावरण के प्रति संचेतना जागृत हुयी। साथ ही १७ वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय उद्यमियों ने अपनी कलाकृति, दस्तकारी व कौशलता के बल पर अनेक वस्तुएं विदेशों को निर्यात करना आरम्भ कर दिया था। भारत में आधुनिक कारखाना प्रणाली की शुरूआत सन् १९५० में हुई। १९ वीं शताब्दी का अंतिम चरण एक ऐसा स्वर्णिम समय था, जब टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने भारत ही नहीं विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी अग्रणी भूमिका प्रस्तुत कर औद्योगिक जगत में एकाधिकार जमा लिया। हमारे देश में उद्यमिता विकास की गति को प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ावा मिला। इस अवधि में नये उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों का

पुनर्निर्माण हुआ। औद्योगिक प्रगति के प्रमुख केन्द्र मुम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई व कानपुर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए तेजी से प्रयास किये गये। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नीतिगत, कार्यात्मक और संस्थागत उपायों पर बल दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में सरकार का पहला महत्वपूर्ण कदम १९४८ में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा था। इस नीति में आधारभूत उद्योगों की स्थापना व निजी उद्यमियों के लिए अनेक क्षेत्र सुरक्षित रखे। उद्यमीय कार्यों एवं व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक वाणिज्यिक नीतियों का निर्धारण किया। साथ ही औद्योगिक नीति व लाइसेन्स प्रणाली का सरलीकरण भी किया गया। महिला उद्यमियों में उद्यमीय प्रवृत्ति को बढावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए।

प्रस्तुत लेख के उद्देश्य-

१. भारत में उद्यमिता विकास की स्थिति का अध्ययन।

२. भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का अध्ययन।

३. भारत में उद्यमिता विकास की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन।

४. भारत में उद्यमिता विकास की प्रगति के लिए सुझाव देना।

भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम- किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। उद्यमीय क्षमताओं के द्वारा ही तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसके लिए ऐसे उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा प्रभावी उद्यमशीलता वर्ग का विकास हो, ताकि आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके। उद्यमिता एक वृत्ति है, जो मां के पेट से उत्पन्न नहीं होती, वरन् समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण जन्य स्थिति से निर्मित और विकसित होती है। इसलिए कहा जाता है, कि '**उद्यमी होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं।**' उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से तात्पर्य उन सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक निजी क्षेत्रों या सरकारी प्रयासों से है, जो उद्यमशीलता के विकास हेतु आयोजित किये जाते हैं। अर्थात् ऐसे प्रयासों से है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में उद्यमिता की वृत्ति का विकास किया जाता है। व्यक्ति के मन में दृढ़ निश्चय उत्पन्न करके उसे उद्यमिता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसकी आंतरिक शक्ति का विकास किया जाता है। ताकि वह सफल उद्यमी बन सके। अपनी सम्पूर्णता में उद्यमिता विकास कार्यक्रम मानव संसाधन विकास का पर्याय है। मूल रूप से तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम पहली पीढ़ी के उद्यमियों का निर्माण करते हैं। अर्थात् जिन्होने कभी व्यवसाय का संचालन करना नहीं जाना, व्यापार की व्यवहारिक गणित का जिन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उनमें व्यवसाय करने का साहस उत्पन्न कर सफल व्यवसायी बनाना ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य ध्येय

है। भारत सरकार ने उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभिन्न उपाय किये है। प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं।

१. **औद्योगिक नीति प्रस्ताव-** योजनाबद्ध आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास की क्रिया में सरकार का पहला कदम सन् १९४८ में औद्योगिक नीति की घोषणा किया जाना था। इस नीति ने आधारभूत उद्योगों की स्थापना व निजी उद्यमियों के लिए अनेक क्षेत्र सुरक्षित रखे।

२. **कुशल वाणिज्यिक नीतियां-** उद्यमीय कार्यों व व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक वाणिज्यिक नीतियों का निर्माण किया। जैसे- मौद्रिक नीति, कर नीति, आयात निर्यात नीति, मूल्य नीति व लाइसेन्स नीति आदि।

३. **औद्योगिक लाइसेन्स प्रक्रिया का सरलीकरण-** भारत सरकार ने नवीन उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के ध्येय से समय समय पर औद्योगिक लाइसेन्स नीति में आवश्यक परिवर्तन किये। लाइसेन्स नीति में सुधार व इससे संबंधित प्रक्रिया को सरलीकृत करने का ध्येय उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है।

४. **समितियों का गठन-** केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न उद्यमियों की समस्याओं का अध्ययन कर आवश्यक परामर्श देने के लिए सम्भावित उद्यमियों की खोज करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशील प्रवृत्तियों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया।

५. **व्यावसायिक एवं तकनीकि शिक्षा का विकास-** भारत सरकार ने नये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए विभिन्न व्यवसायिक व तकनीकि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है।

६. **कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन-** उद्यमिता का विकास एवं इनसे सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर समाधान खोजने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न सम्मेलनों व विचारगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करती है। इस संबंध में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान विशेष योगदान दे रहा है।

७. **प्रशिक्षण कार्यक्रम-** भारत सरकार उद्यमियों के हितार्थ उनके मानसिक, शारीरिक एवं कार्य निष्पादन सम्बंधी विकास के लिए सरकार विभिन्न संस्थाओं, प्रबंध संस्थाओं एवं तकनीकि स्कूलों के माध्यम से समय समय पर उद्यमीय प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम विधियों का आयोजन करती है।

८. **परामर्श सहायता कार्यक्रम-** सरकार उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं यथा परियोजना निर्माण, उत्पादन की नवीन प्रवृत्तियों, गुणवत्ता सुधार, संयन्त्र अभिन्यास, कच्चे माल की प्राप्ति, मशीनों उपकरणों का रखरखाव, श्रम विकास आदि के बारे में परामर्श देती है।

भारत में उद्यमिता विकास सहायतार्थ संगठन– भारत सरकार ने उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन एवं उद्यमियों की सहायता करने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। ये संस्थान उद्यमियों को प्रशिक्षण देने, व्यवसायियों को परामर्श देने, संगोष्ठियों का आयोजन करने, विभिन्न अनुसंधान आदि अनेक कार्य करते हैं। ऐसे संगठनों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। केन्द्रीय स्तर के संगठन, राज्य स्तरीय संगठन एवं अनुसंधान, परीक्षण एवं मानक संगठन। इनमें कुछ प्रमुख संगठन निम्न लिखित हैं-

१. **राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लद्यु व्यवसाय विकास संस्थान**– राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लद्यु व्यवसाय विकास संस्थान का गठन जुलाई १९८३ में उद्योग मन्त्रालय के आधीन किया गया था। इसका केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख उद्देश्य उद्यमिता एवं लद्यु व्यवसाय के विकास में संलग्न संस्थाओं को मार्गदर्शन करना एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुसंधान करवाना है।

२. **राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मण्डल**– राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मण्डल देश में उद्यमिता के विकास के लिए नीति निर्धारण करने वाली शीर्ष संस्था है। इसका मुख्य कार्य नीति निर्देशन एवं मार्गदर्शन करना है। इसके द्वारा प्रषित सिफारिशें एवं सुझावों को क्रियान्वित करने का कार्य राष्ट्रीय साहस एवं लद्यु व्यापार विकास संस्थान करता है।

३. **भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद**– भारत में उद्यमिता विकास के लिए संस्थागत मूलभूत ढ़ॉचा विकसित करने के लिए विकास बैंक ने अन्य संस्थाओं के सहयोग से अहमदाबाद में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की है। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य अल्प विकसित राज्यों में उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम चलाना एवं उद्यमिता विकास कार्यों के लिए व्यापक कार्य योजनाएं तैयार करना है।

४. **अखिल भारतीय हस्तशिल्प वोर्ड**– भारत में हस्तशिल्प के उद्योगों का विकास करने के लिए भारत सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प वोर्ड की स्थापना की। इस वोर्ड के कार्यालय सभी राज्यों में स्थित हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देना एवं उनके उत्पादन का विपणन करना है।

५. **राष्ट्रीयकृत, वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक**– भारत विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंकों के द्वारा उद्यमियों के लिए उनकी आवश्यकता, परियोजना तथा कौशल के आधार पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में अनेक बैंकों द्वारा लद्यु उद्योग इकाईयों को व्यवसायिक उद्देश्यों हेतु ऋण प्रदान किये जाते हैं।

६. **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग**– खादी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु सरकार ने १९५६ में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की है। वर्तमान में ९६ उद्योग इसके कार्यक्षेत्र में हैं। इसका

मुख्यालय मुबंई में है। एवं प्रत्येक राज्य में इसके कार्यालय हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग महिला उत्पादों के लिए विशेषत: उपयोगी है।

७. **राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान-** राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सन् १९६० में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका मुख्य कार्य लघु साहसियों एवं प्रबंधकों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना है।

८. **अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड-** अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना १९५४ में एक सलाहकार समिति के रूप में की गई थी। यह वोर्ड लघु उद्योगों के विकास हेतु नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। इस वोर्ड का अध्यक्ष मंत्री होता है।

९. **जिला उद्योग केन्द्र-** भारत सरकार ने अपने औद्योगिक नीति प्रस्ताव १९७७ में जिला मुख्यालयों पर जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया ताकि नये उद्यमी को नए उद्योगों की स्थापना की सभी सुविधाएं जैसे- भूमि, बिजली, पानी, वित्त एवं विपणन आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें।

१०. **आविष्कार संवर्धन वोर्ड-** आविष्कार संवर्धन वोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा १९६० में की गई। इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पियों एवं तकनीशियानों को नये नये आविष्कारो के लिए प्रोत्साहित करना है।

भारत में उद्यमिता विकास की प्रमुख समस्याएं एवं चुनौतियां- भारत में उद्यमिता के समुचित विकास के क्रम में अनेक समस्याऐं व बाधाएं हैं। ये समस्याएं उद्यमशील प्रवृत्तियों व स्वस्थ्य औद्योगिक विकास के लिए चुनौतियों के रूप में भी प्रकट होती हैं।

१. **पूंजी की समस्या-** उद्यमिता विकास की प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या पूंजीगत साधनों का आभाव व इनकी अपर्याप्ता के रूप में प्रकट होती है। साथ ही व्यवसायिक उपक्रमों में कार्यशील पूंजी की दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था भी पूंजी सम्बंधी समस्याओं को बढ़ावा देती है।

२. **कुशल प्रबंधकों का आभाव-** प्राय: योग्य कुशल व प्रशिक्षित प्रबंधकों के मार्गदर्शन के आभाव के कारण हमारे देश उपक्रमों की कार्यप्रणाली व निष्पादन क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं। अत: उद्यमिता विकास में कुशल प्रबंधकों का न होना हमारे देश की प्रमुख बाधा है।

३. **व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का आभाव-** हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता के आभाव एवं अपर्याप्तता के कारण उद्यमिता का विकास अवरूद्ध है। अभी तक शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र सामान्यत: शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।

४. **बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा-** हमारे देश में प्राय: सभी औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन, रोजगार, श्रम विभाजन, विनियोजन व बाजार संबंधी पहलुओं के अंतर्गत बड़े घरानों का अधिपत्य रहा है। इसी कारण लघु व कुटीर व्यवसायिक इकाईयों को अपनी पहचान व अस्तित्व बनाने व प्रतिस्पर्धा सुदृढ़ता की प्राप्ति के अनुकूल अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जिस कारण उद्यमशील प्रवृत्तियों का विकास नहीं हो पा रहा है।

५. **कर एवं व्यय भार की अधिकता-** हमारे देश में कर की दरें इतनी अधिक हैं, कि करों के भारी दबाव के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। साथ ही उद्योग की स्थापना, संचालन व विकास की प्रक्रिया में विभिन्न औपचारिकताएं अत्यधिक व्ययपूर्ण होती हैं। ऐसी स्थिति में नए उद्यमी हतोत्साहित होते हैं।

६. **प्रेरक तत्वों का आभाव-** उद्यमिता विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रेरक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसे तत्वों की काफी कमी है। जिस कारण नवीन उद्यमशीलता विकसित नहीं हो पाती।

७. **सरकारी नीतियां-** उद्यमिता के विकास के लिए सरकारी नीतियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लेकिन हमारे देश में सरकारी नीतियां व्यवहारिक एवं प्रेरणास्पद स्वरूप प्रदान नहीं कर पाई है। अत: उद्यमियों को श्रेष्ठ वातावरण के अवसर नहीं मिल पाते हैं।

भारत में उद्यमिता विकास हेतु सुझाव- भारत में उद्यमिता विकास की धारणाएं औद्योगिक क्षेत्रों में सदैव नवीनता एवं आधुनिकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती रहीं हैं। अपनी पुरातन व परम्परावादी विचारों, मान्यताओं के माध्यम से विकासशील अवस्थाओं का सामना करती हुईं उद्यमशील प्रवृत्तियां एवं औद्योगिक विकास की दिशाएं निश्चित ही उदासीनता व अनेक बाधक तत्वों के साथ सामंजस्य करती हुइ आगे बढ़ रही हैं। वस्तुत: उद्यमिता के समुचित विकास के क्रम में, बुनियादी तौर पर युवा पीढ़ी में उद्यमीय मनोवृत्तियों व आकांक्षाओं को प्रेरित करना आवश्यक है, ताकि उद्यमीय संस्कृति की स्थापना की जा सके। हमारे देश में उद्यमिता के तीव्र विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं-

१. युवाओं में, परिवार व समाज के वातावरण में उद्यमीय प्रवृत्तियों का बढ़ावा देना होगा।

२. सामाजीकरण की प्रक्रिया में स्वाबलंबन, कर्मशीलता, दृढ़ निश्चय, परिश्रम एवं अनुशासनबद्ध क्रियाओं को बढ़ावा देना होगा।

३. देश की शिक्षा पद्धति व शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों को रोजगार व साहस अभिमुखी बनाया जाना चाहिए।

४. भारत में उद्यमिता विकास के लिए शोध व अनुसंधान की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

५. सरकारी व अन्य संस्थाओं द्वारा स्वरोजगार योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।
६. भारत में उद्यमिता विकास के अनुकूल वातावरण के लिए उद्यमिता साहित्य का प्रचार व प्रकाशन किया जाना चाहिए।
७. भारत में उद्यमिता विकास के लिए सरकार द्वारा दीर्घकालीन योजनाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष- किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उद्यमिता का निर्णायक एवं महत्वपूर्ण योगदान होता है। उद्यमीय प्रवृत्तियों एवं कार्यों के कारण ही देश के संसाधनों व आय सम्पदा की उपलब्धता, संसाधनों को उप्तादक कार्यों में लगाना, नयी तकनीक, नयी प्राविधयों एवं नये दृष्टिकोणों को राष्ट्रहित में काम में लेना एवं अन्यानेक साहसिक निर्णयों द्वारा सृजनशीलता एवं क्रियात्मकता का निर्माण किया जाना संभव होता है। भारत के संदर्भ में कहा जाए तो यहां उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक दशाओं की अत्यन्त कमी है। जिस कारण यहां उद्यमिता विकास की गति काफी धीमी है। भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विभिन्न कदम उठाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची-

१. माथुर, डॉ. एस. पी. (२००८), भारत में उद्यमिता विकास, हिमालया पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली,।
२. जैन डॉ. पी. सी. एवं शर्मा डॉ. एन. एल. (२००६), उद्यमिता के मूल आधार, रमेश बुक डिपो, जयपुर।
3. A.N. Desai, 1980 Enterpreneureship and Environment, Ashish Publication House, New Delhi.
4. N.P. Singh, 1985 Emerging Trends in Entrepreneurship Development, Theories and Prectice, IFDM, New Delhi.
5. V.R. Gaikwad, 1974, Enterpreneurship Concepts and Approaches, Indian Institute of Management, Ahemdabad.
6. Basant Desai, 1999 Small Scale Industries and Enterpreneurship, Himalya Publishing House, Bombey.